

"यूझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेदेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 12 अप्रैल 2026 रविवार

सम्पादकीय

खतरे में भविष्य

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन नौनिहालों को हम देश का भविष्य मानते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे आज बहुस्तरीय जोखिम के बीच से गुजर रहे हैं। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के अनेक रूप के अलावा बाल तस्करी का संजाल आज इस कदर जटिल होता जा चुका है कि इससे निपटना सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि इस अपराध को काबू में करना और बच्चों को इस खतरे से बचाना सरकारी की अनिवार्य जिम्मेदारी और सबसे ऊपर की प्राथमिकता में दर्ज होना चाहिए। मगर हालत यह है कि देश के सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देना पड़ रहा है कि वे बच्चों के खिलाफ इस अपराध को गंभीरता से लें।

भारत में बच्चों के लापता होने के मामले चिंताजनक हैं, 31 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच देश में 33,577 बच्चे गायब हुए, जिनमें से 7,777 अब तक नहीं मिले हैं। दिल्ली में 2026 के शुरुआती दिनों में ही 800 से अधिक लोग लापता हुए, जिनमें से कई बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए केंद्र को सक्रिय गिरोह की जांच करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में बाल तस्करी के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई और कहा कि संगठित गिरोह देशभर में सक्रिय हैं और अगर राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों ने तुरंत प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि बाल तस्करी के फलते जाल पर शीर्ष अदालत के सख्त रुख के बावजूद कई राज्यों ने अब तक न जरूरी रपट तैयार की है और न ही समितियां बनाई हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए स्वामाधिक ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लापरवाह रवैये पर नाराजगी जताई। दरअसल, करीब एक वर्ष पहले अदालत ने अपने एक फैसले में संगठित तस्करी के जाल को तोड़ने के लिए कई संस्थागत सुधारों के निर्देश दिए थे। इनमें तस्करी के मामलों में छह महीने के भीतर हर रोज सुनवाई करना, मानव तस्करी रोधी इकाइयों को मजबूत करना और जांच प्रक्रिया में सुधार करना शामिल था।

अदालत ने राज्यों को यह निर्देश दिया था कि वे तस्करी के संभावित संवेदनशील स्थानों की पहचान और निगरानी के लिए राज्यस्तरीय समितियां बनाएं और लापता बच्चों के मामलों को तस्करी मान कर जांच शुरू करें। मगर इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के रुख का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई राज्यों ने अभी तक तय प्रारूप में रपट तक दाखिल नहीं की है। सरकारी तंत्र में इस इच्छाशक्ति के अभाव और उदासीनता की वजह क्या यह है कि जो बच्चे तस्करी का शिकार हो जाते हैं, उनमें ज्यादातर समाज के गरीब और कमजोर तबके से आते हैं?

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि देश में बाल तस्करी का संकट पिछले कुछ वर्षों के दौरान किताना गहरा गया है। खासतौर पर काठिंड महामारी के बाद बच्चों के लापता होने के मामलों में काफी तेजी दर्ज की गई। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति ज्यादा गंभीर है। सही है कि लापता होने वाले तमाम बच्चों में से कुछों को पुलिस खोज लेती है, लेकिन उनमें से बहुतों को कोई खबर नहीं मिलती। क्या है कि जिन बच्चों को नहीं खोजा जा पाता, वे सवाल जाते हैं और उनके साथ क्या होता है।

यह समझना मुश्किल नहीं है कि देश भर में जो बच्चे गायब हो जाते हैं, उन्हें बाल मजदूरी से लेकर यौन शोषण और अपराध की दुनिया के अंतहीन दलदल में झोंक दिया जाता है। एक रिपोर्ट अपने बच्चे के लापता होने के बाद किफा दंश और दुख से गुजरता है, यह शायद बताने की जरूरत नहीं है। मगर कोई भी समाज और सत्ता बच्चों की तस्करी के मुद्दे को लेकर अगर गंभीर नहीं है, तो यह एक तरह से अपने ही भविष्य की त्रासदी को नजरअंदाज करना है।

यूपी में मतदाता सूची के आकड़े और राजनीति

-निरज कुमार दूबे-

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद जारी अंतिम आंकड़ों ने राज्य की चुनावी तस्वीर में बड़ा बदलाव सामने रखा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीद्वीर सिन्हा द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार लगभग दो करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। यह संख्या अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य की कुल जनसंख्या तथा चुनावी भागीदारी पर गहरा प्रभाव डालने वाली है।

हम आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान कुल 166 दिनों तक चला, जिसकी शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी। उस समय राज्य में कुल 15 करोड़ 34 लाख मतदाता पंजीकृत थे। प्रारंभिक चरण के बाद छह जनवरी को प्रकाशित प्रारूप सूची में यह संख्या घटकर बाहर करोड़ पचास लाख रह गई थी। हालांकि इसके बाद आमतौर पर, चुनावी और सत्यान की लंबी प्रक्रिया के पश्चात अंतिम सूची में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 थे। मतदाता दंड किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे पंद्रह दिनों के भीतर संबंधित जिला अधिकारियों के समक्ष अपील कर सकते हैं। इसके बाद भी समाधान न मिलने पर दूसरी अपील प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारी के पास की जा सकती है।



और अंत में नया मतदाता बने के लिए प्रस्ताव छह मरा जा सकता है। यदि जिलावार आंकड़ों पर नजर आने तो राजधानी लखनऊ में सबसे अधिक लोख चौदह हजार नाम हटाए गए, जो लगभग 22.79 प्रतिशत है। इसके बाद प्रयागराज में आठ लाख छब्बीस हजार, कानपुर में छह लाख सत्तासी हजार, आगरा में छह लाख सतीस हजार, गाजियाबाद में पांच लाख चौदह हजार, मेरठ में पांच लाख छह हजार और बरेली में चार लाख छठान हजार नाम हटाए गए। विधानसभा क्षेत्रों में साहियाबाद में तीन लाख सोलह हजार नाम हटाए जाने के साथ यह सूची में सबसे ऊपर रहा, जबकि नोएडा, लखनऊ उत्तर, आगरा केंद्र और इलाहाबाद उत्तर भी प्रमुख थे। छह जनवरी से दस अप्रैल के

बीच कुल आठ लाख पंद्रह हजार नौ सौ छियानवे मतदाताओं के नाम हटाए गए। इनमें से तीन लाख पचास हजार से अधिक लोगों ने नोटिस देकर जमा नहीं दिया, लगभग तीन लाख अर्द्धसह हजार लोग स्थानांतरित पाए गए, उनसह हजार से अधिक नाम बूट प्रक्रिया के कारण हटाए गए, पचास हजार से अधिक मतदाता मृत पाए गए और दो हजार से अधिक लोग आयु या नगरिकाता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तीन करोड़ छब्बीस लाख से अधिक नोटिस जारी किए गए। लगभग एक करोड़ चार लाख मतदाता ऐसे पाए गए जिनकी जांचकरी पूरी तरह से मेल नहीं खा रही थी, जबकि दो करोड़ 22 लाख मतलों में तालिके विसंमति थीं। चौदह जनवरी से नोटिस जारी

होने शुरू हुए और 31 जनवरी से सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होकर 27 मार्च तक पूरी की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश मतदाता विलोपन प्रतिक्रिया के मामले में दूसरे स्थान पर रहा, जहां यह आंकड़ा तेरह दशकभर चौबीस प्रतिशत रहा। इससे आगे गुजरात रहा, जबकि अन्य राज्यों में यह प्रतिशत अर्धपचास तक था। तीसरे स्थान पर बिहार और ओडिसा के आंध्र पर एक लाख बीस हजार से अधिक नाम हटाए गए। इनमें अधिकतर मामले भ्रष्ट, स्थायी स्थान परिवर्तन या अन्य पंजीकरण से जुड़े थे। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भी सक्रिय भागीदारी रही। पांच प्रमुख बंडों के अलावा नौ सौ चार बंडों का आयोग जिला स्तर पर किया गया।

की संख्या सत्रह लाख तिरसठ हजार तीन सौ साठ है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रारूप और अंतिम सूची के बीच कुल चौरासी लाख अर्द्धसह हजार सात सौ सत्सठ मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। इसमें बयालीस लाख से अधिक पुरुष और लगभग इतने ही महिला मतदाता शामिल हैं। इससे लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो आठ सौ चौबीस से बढ़कर आठ सौ चौतीस हो गया है। यह है कि इससे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज सबसे आगे रहा, जहां तीन लाख उन्तीस हजार से अधिक नए मतदाता जुड़े। इसके बाद लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर प्रमुख हैं। इससे लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो आठ सौ चौबीस से बढ़कर आठ सौ चौतीस हो गया है। यह है कि इससे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज सबसे आगे रहा, जहां तीन लाख उन्तीस हजार से अधिक नए मतदाता जुड़े। इसके बाद लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर प्रमुख हैं। इससे लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो आठ सौ चौबीस से बढ़कर आठ सौ चौतीस हो गया है।

लखनऊ, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में अक्टूबर 2025 की तुलना में लगभग 19 से 23 प्रतिशत तक मतदाता घटे हैं। यह क्षेत्र हैं जहां पिछले चुनावों में भाजपा का मजबूत प्रभाव रहा है। विधानसभा स्तर पर भी साहियाबाद, नोएडा, लखनऊ उत्तर पर बड़ी संख्या में मतदाता कम हुए। आंकड़ों के अनुसार जिन सीटों पर एक लाख से अधिक वोट पड़े हैं, उनमें अधिकतर पर भाजपा का कब्जा है। इसके अलावा, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गिरावट अर्धपचास तक रही, जहां लगभग 9 से 14 प्रतिशत वोट की कमी दर्ज की गई है। (दस लाख के आयोग जिला स्तर पर किया गया।)

नेपाल की नई सरकार में शिक्षा के फैसले

-डॉ. शैलेश शुक्ला-

दक्षिण एशिया के छोटे लोकतंत्र राजनीतिक रूप से अत्यंत सक्रिय देश नेपाल में हाल ही में नई नई सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय और पहलें सामने रखी हैं जिनकी चर्चा न केवल वहाँ की आंतरिक राजनीति में, बल्कि पड़ोसी देशों में भी हो रही है। सीमित संसाधनों, जटिल भौगोलिक परिस्थितियों और राजनीतिक अस्थिरता के त्वे इतिहास के बावजूद नेपाल में शासन के नए प्रयोग यह संकेत देते हैं कि यह राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट हो तो अपेक्षाकृत कम संसाधनों में भी जनतंत्रिकी नीतियों की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। यही कारण है कि यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है क्या भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को नेपाल की इन पहलों से कुछ सीखने की आवश्यकता है?

नेपाल की नई सरकार की सबसे अधिक चर्चा में रही पहल शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है, जहाँ निजी कोचिंग संस्थानों और निजी स्कूलों के संचालन पर सख्त नियंत्रण और नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। यद्यपि इन संस्थानों को पूरी तरह बंद करने जैसी अतिवादी व्याख्याएँ कई जगह सामने आईं, परंतु वास्तविकता यह है कि सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को सीमित करने और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कठोर नियम लागू किए हैं। इस नीति का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा केवल आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक सीमित न रह जाए, बल्कि समाज के सभी वर्गों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

यह दृष्टिकोण उस व्यापक चिंता को प्रतिबिम्बित करता है, जो आज पूरे दक्षिण एशिया में शिक्षा के बढ़ते निजीकरण को लेकर व्यक्त की जा रही है। नेपाल की इस पहल का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि शिक्षा को केवल 'बेना' नहीं, बल्कि सार्वजनिक अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। जहाँ निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान अनियंत्रित रूप से बढ़ते हैं तो वे एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था खड़ा कर देते हैं, जिसमें गुणवत्ता और अक्सर दोनों ही आर्थिक अभाव पर निर्भर हो जाते हैं। नेपाल सरकार ने इस असंतुलन को पहचानते हुए सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास किया है, यह यह प्रयोग सफल होता है, तो यह पूरे क्षेत्र के लिए एक उदाहरण बन सकता है।

इसके अतिरिक्त, नेपाल सरकार ने स्वास्थ, प्रशासनिक पारदर्शिता और स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए एक नया कानून पारित किया है, जो सरकारों को अधिकारों को संचालन, अनुवर्धन, मूल्यांकन, निगरानी और डिजिटल माध्यमों में कदम उठाने को बढावा देता है। यह प्रयोग शासन को अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। यह तब विशेष रूप से उल्लेखनीय है जबकि अपेक्षाकृत छोटे देश ने सीमित संसाधनों के बावजूद शासन सुधार की दिशा में ठोस इच्छाशक्ति दिखाई है।



नेपाल की नई सरकार की सबसे अधिक चर्चा में रही पहल शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है, जहाँ निजी कोचिंग संस्थानों और निजी स्कूलों के संचालन पर सख्त नियंत्रण और नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। यद्यपि इन संस्थानों को पूरी तरह बंद करने जैसी अतिवादी व्याख्याएँ कई जगह सामने आईं, परंतु वास्तविकता यह है कि सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को सीमित करने और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कठोर नियम लागू किए हैं। इस नीति का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा केवल आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक सीमित न रह जाए, बल्कि समाज के सभी वर्गों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

नेपाल की नई सरकार की सबसे अधिक चर्चा में रही पहल शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है, जहाँ निजी कोचिंग संस्थानों और निजी स्कूलों के संचालन पर सख्त नियंत्रण और नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। यद्यपि इन संस्थानों को पूरी तरह बंद करने जैसी अतिवादी व्याख्याएँ कई जगह सामने आईं, परंतु वास्तविकता यह है कि सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को सीमित करने और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कठोर नियम लागू किए हैं। इस नीति का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा केवल आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक सीमित न रह जाए, बल्कि समाज के सभी वर्गों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

नेपाल की नई सरकार की सबसे अधिक चर्चा में रही पहल शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है, जहाँ निजी कोचिंग संस्थानों और निजी स्कूलों के संचालन पर सख्त नियंत्रण और नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। यद्यपि इन संस्थानों को पूरी तरह बंद करने जैसी अतिवादी व्याख्याएँ कई जगह सामने आईं, परंतु वास्तविकता यह है कि सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को सीमित करने और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कठोर नियम लागू किए हैं। इस नीति का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा केवल आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक सीमित न रह जाए, बल्कि समाज के सभी वर्गों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

इसी प्रकार, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत में असमानता एक बड़ी समस्या है। शहरी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय निजी अस्पताल उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ भी कई बार अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो इससे व्यापक स्तर पर जनस्वास्थ्य में सुधार संभव है। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी देश की प्रगति, पंचनम तंत्र से जुड़ी बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह पाएगी, बल्कि यह हड्डियों, रक्तदान प्रणाली और प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यह शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है और यह कई कैंसर और मेटाबोलिक विकार को भी पार कर चुका है। इससे मरिस्तक पर भी गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ गया है। कारण यह है कि अब वातावरण में मानक से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। यह मानसिक विकार के साथ-साथ बच्चों की बुद्धिमान भी पर असर डाल रहा है। बुनियादी कोशिका-अभ्यन्तन प्रभावित करे कि वायु प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास के लिए गंभीर खतरा है। वे जन्मते ही बुद्धिमान, वादाशर, एकतावादी और सकारित की क्षमता को कम कर देता है। प्रदूषित वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा डालते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी भाषा, कोश, मूल नियंत्रण और व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उच्च वायु प्रदूषण और गंदी हवा में रहने वाले बच्चों के आईव्यू स्कॉर में महत्वपूर्ण बच्चों के कारण बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उनकी सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहार पर नकारात्मक असर डालता है। यही नहीं, अत्यधिक संक्रियता, खराब स्मृति और स्थान कोटिड करने में कठिनाई भी पैदा हो सकती है। यह फिर हम वर्तमान व्यवस्था के साथ समझौता करने से रोकता है, यह प्रश्न केवल सरकारी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

नेपाल की नई सरकार द्वारा उठाए गए कदम हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हम अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तैयार हैं। क्या हम शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में वास्तविक सुधार के लिए साहसिक निर्णय लेने को तैयार हैं, या फिर हम वर्तमान व्यवस्था के साथ समझौता करने से रोकते हैं, यह प्रश्न केवल सरकारी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

जान लेवा होता वायु प्रदूषण

-ज्ञानेन्द्र रावत-

वैज्ञानिकों ने कहा है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 (सूक्ष्म कण) के कारण पूरी दुनिया की आबादी को 65 अरब आईव्यू अंक का नुकसान हो रहा है। नेपाल की तरह यह शरीर के माध्यम से सीधे मरिस्तक तक पहुंच रहे हैं। वायु प्रदूषण अब एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुका है। इसका असर उच्च हृदय, फेफड़े, सांस, त्वचा, दमा, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह पाएगी, बल्कि यह हड्डियों, रक्तदान प्रणाली और प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यह शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है और यह कई कैंसर और मेटाबोलिक विकार को भी पार कर चुका है। इससे मरिस्तक पर भी गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ गया है। कारण यह है कि अब वातावरण में मानक से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। यह मानसिक विकार के साथ-साथ बच्चों की बुद्धिमान भी पर असर डाल रहा है। बुनियादी कोशिका-अभ्यन्तन प्रभावित करे कि वायु प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास के लिए गंभीर खतरा है। वे जन्मते ही बुद्धिमान, वादाशर, एकतावादी और सकारित की क्षमता को कम कर देता है। प्रदूषित वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा डालते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी भाषा, कोश, मूल नियंत्रण और व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उच्च वायु प्रदूषण और गंदी हवा में रहने वाले बच्चों के आईव्यू स्कॉर में महत्वपूर्ण बच्चों के कारण बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उनकी सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहार पर नकारात्मक असर डालता है। यही नहीं, अत्यधिक संक्रियता, खराब स्मृति और स्थान कोटिड करने में कठिनाई भी पैदा हो सकती है। यह फिर हम वर्तमान व्यवस्था के साथ समझौता करने से रोकता है, यह प्रश्न केवल सरकारी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है।



वैज्ञानिकों ने कहा है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 (सूक्ष्म कण) के कारण पूरी दुनिया की आबादी को 65 अरब आईव्यू अंक का नुकसान हो रहा है। नेपाल की तरह यह शरीर के माध्यम से सीधे मरिस्तक तक पहुंच रहे हैं। वायु प्रदूषण अब एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुका है। इसका असर उच्च हृदय, फेफड़े, सांस, त्वचा, दमा, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह पाएगी, बल्कि यह हड्डियों, रक्तदान प्रणाली और प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यह शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है और यह कई कैंसर और मेटाबोलिक विकार को भी पार कर चुका है। इससे मरिस्तक पर भी गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ गया है। कारण यह है कि अब वातावरण में मानक से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। यह मानसिक विकार के साथ-साथ बच्चों की बुद्धिमान भी पर असर डाल रहा है। बुनियादी कोशिका-अभ्यन्तन प्रभावित करे कि वायु प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास के लिए गंभीर खतरा है। वे जन्मते ही बुद्धिमान, वादाशर, एकतावादी और सकारित की क्षमता को कम कर देता है। प्रदूषित वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा डालते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी भाषा, कोश, मूल नियंत्रण और व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उच्च वायु प्रदूषण और गंदी हवा में रहने वाले बच्चों के आईव्यू स्कॉर में महत्वपूर्ण बच्चों के कारण बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उनकी सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहार पर नकारात्मक असर डालता है। यही नहीं, अत्यधिक संक्रियता, खराब स्मृति और स्थान कोटिड करने में कठिनाई भी पैदा हो सकती है। यह फिर हम वर्तमान व्यवस्था के साथ समझौता करने से रोकता है, यह प्रश्न केवल सरकारी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

वैज्ञानिकों ने कहा है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 (सूक्ष्म कण) के कारण पूरी दुनिया की आबादी को 65 अरब आईव्यू अंक का नुकसान हो रहा है। नेपाल की तरह यह शरीर के माध्यम से सीधे मरिस्तक तक पहुंच रहे हैं। वायु प्रदूषण अब एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुका है। इसका असर उच्च हृदय, फेफड़े, सांस, त्वचा, दमा, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह पाएगी, बल्कि यह हड्डियों, रक्तदान प्रणाली और प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यह शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है और यह कई कैंसर और मेटाबोलिक विकार को भी पार कर चुका है। इससे मरिस्तक पर भी गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ गया है। कारण यह है कि अब वातावरण में मानक से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। यह मानसिक विकार के साथ-साथ बच्चों की बुद्धिमान भी पर असर डाल रहा है। बुनियादी कोशिका-अभ्यन्तन प्रभावित करे कि वायु प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास के लिए गंभीर खतरा है। वे जन्मते ही बुद्धिमान, वादाशर, एकतावादी और सकारित की क्षमता को कम कर देता है। प्रदूषित वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा डालते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी भाषा, कोश, मूल नियंत्रण और व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उच्च वायु प्रदूषण और गंदी हवा में रहने वाले बच्चों के आईव्यू स्कॉर में महत्वपूर्ण बच्चों के कारण बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उनकी सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहार पर नकारात्मक असर डालता है। यही नहीं, अत्यधिक संक्रियता, खराब स्मृति और स्थान कोटिड करने में कठिनाई भी पैदा हो सकती है। यह फिर हम वर्तमान व्यवस्था के साथ समझौता करने से रोकता है, यह प्रश्न केवल सरकारी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

वैज्ञानिकों ने कहा है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 (सूक्ष्म कण) के कारण पूरी दुनिया की आबादी को 65 अरब आईव्यू अंक का नुकसान हो रहा है। नेपाल की तरह यह शरीर के माध्यम से सीधे मरिस्तक तक पहुंच रहे हैं। वायु प्रदूषण अब एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुका है। इसका असर उच्च हृदय, फेफड़े, सांस, त्वचा, दमा, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह पाएगी, बल्कि यह हड्डियों, रक्तदान प्रणाली और प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यह शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है और यह कई कैंसर और मेटाबोलिक विकार को भी पार कर चुका है। इससे मरिस्तक पर भी गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ गया है। कारण यह है कि अब वातावरण में मानक से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। यह मानसिक विकार के साथ-साथ बच्चों की बुद्धिमान भी पर असर डाल रहा है। बुनियादी कोशिका-अभ्यन्तन प्रभावित करे कि वायु प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास के लिए गंभीर खतरा है। वे जन्मते ही बुद्धिमान, वादाशर, एकतावादी और सकारित की क्षमता को कम कर देता है। प्रदूषित वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा डालते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी भाषा, कोश, मूल नियंत्रण और व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उच्च वायु प्रदूषण और गंदी हवा में रहने वाले बच्चों के आईव्यू स्कॉर में महत्वपूर्ण बच्चों के कारण बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उनकी सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहार पर नकारात्मक असर डालता है। यही नहीं, अत्यधिक संक्रियता, खराब स्मृति और स्थान कोटिड करने में कठिनाई भी पैदा हो सकती है। यह फिर हम वर्तमान व्यवस्था के साथ समझौता करने से रोकता है, यह प्रश्न केवल सरकारी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

वैज्ञानिकों ने कहा है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 (सूक्ष्म कण) के कारण पूरी दुनिया की आबादी को 65 अरब आईव्यू अंक का नुकसान हो रहा है। नेपाल की तरह यह शरीर के माध्यम से सीधे मरिस्तक तक पहुंच रहे हैं। वायु प्रदूषण अब एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुका है। इसका असर उच्च हृदय, फेफड़े, सांस, त्वचा, दमा, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह पाएगी, बल्कि यह हड्डियों, रक्तदान प्रणाली और प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यह शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है और यह कई कैंसर और मेटाबोलिक विकार को भी पार कर चुका है। इससे मरिस्तक पर भी गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ गया है। कारण यह है कि अब वातावरण में मानक से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। यह मानसिक विकार के साथ-साथ बच्चों की बुद्धिमान भी पर असर डाल रहा है। बुनियादी कोशिका-अभ्यन्तन प्रभावित करे कि वायु प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास के लिए गंभीर खतरा है। वे जन्मते ही बुद्धिमान, वादाशर, एकतावादी और सकारित की क्षमता को कम कर देता है। प्रदूषित वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा डालते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी भाषा, कोश, मूल नियंत्रण और व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उच्च वायु प्रदूषण और गंदी हवा में रहने वाले बच्चों के आईव्यू स्कॉर में महत्वपूर्ण बच्चों के कारण बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उनकी सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहार पर नकारात्मक असर डालता है। यही नहीं, अत्यधिक संक्रियता, खराब स्मृति और स्थान कोटिड करने में कठिनाई भी पैदा हो सकती है। यह फिर हम वर्तमान व्यवस्था के साथ समझौता करने से रोकता है, यह प्रश्न केवल सरकारी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

